दैनिक जागरण नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2023

NAME O

नरेला के खाली फ्लैट बिक नहीं रहे, रखरखाव पर सालाना खर्च हो रहे करीब 25 लाख रुपये

राज्य ब्युरो, नई दिल्ली: नरेला में बने डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) के सभी फ्लैट बिक तो पा नहीं रहे हैं, अलबता इनके रखरखाव पर सालाना 25 लाख रुपये खर्च और हो रहा है। आलम यह है कि डीडीए ने अब नरेला के इन खाली पड़े फ्लैटों की सालाना मरम्मत व रखरखाव के लिए ठेकेदार से अनुबंध करने की तैयारी शरू कर दी है।

डीडीए अधिकारियों के अनुसार नरेला की पाकेट चार एवं पांच के सेक्टर-जी7/जी8 में बने फ्लैटों के लिए ठेकेदारों से आवेदन मांगे गए हैं। उन्हें आवेदन जमा करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। तकनीकी निविदा 17 अगस्त को खुलेगी। यह टेंडर 12 माह के लिए जारी होगा और इसके लिए 24,85,420 का अनुमानित

गौरतलब है कि 2022 में डीडीए की खराब आर्थिक हालत की वजह भी इन्हीं फ्लैटों को ही बताया गया था। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार 2014 के बाद से अब तक डीडीए करीब 57 हजार फ्लैट

 नरेला में डीडीए के 25,000 के करीब फ्लैट बनकर हैं तैयार

 पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ६६० से अधिक फ्लैट हुए बुक



नरेला में मेट्रो आने के बाद फ्लैट्स की बुकिंग तेज होने की उम्मीद हैं 🌣 नागरण

आवासीय योजना में ला चुका है। इनमें से करीब 15,500 फ्लैट्स लोगों ने वापस कर दिए या वह बिक नहीं पाए। अकेले नरेला में डीडीए के 25,000 के करीब फ्लैट विभिन्न पाकेटों में बनकर तैयार हैं।

उधर, डीडीए के मुताबिक हाल फिलहाल चल रही डीडीए की पहले आओ पहले पाओ चौथे चरण की

स्कीम को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। इस स्कीम के तहत लोगों ने नरेला में भी 660 से अधिक फ्लैट बुक करवाए हैं। डीडीए को उम्मीद है किं डीएमआरसी के मेट्रो प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यहां के सभी मिर्देट लोगों को पसंद आने लगेंगे स्लैट की बुकिंग तेज गति से

पीएम उदय योजना के लिए बना एप ठप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2019 में दिल्ली की 1731 अनिधकृत कालोनियों में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अभी तक अपेक्षित लक्ष्य को हासिल कर पाने में सफल नहीं हो सकी है। आलम यह है कि लगभग साढ़े तीन वर्ष में भी लगभग सवा 19 हजार लोगों को ही कन्वेंस डीड (सीडी) जारी की जा सकी है। आमजन को जहां डीडीए अधिकारियों से शिकायत है, वहीं डीडीए का कहना है कि प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोशिश

इसी कड़ी में डीडीए ने 14 जुलाई को एक एप जारी किया था। गूगल प्ले स्टोर के साथ एप डाउनलोड करने का लिंक डीडीए की पीएम-उदय वेबसाइट पर भी दिया गया था। एप को अब तक 10 हजार से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं।

| चार अगस्त, 202 पीएम उदय योजन | |
|---------------------------------|----------|
| आवेदन आए | 1,14,769 |
| आवेदनों पर कार्रवाई | 1,14,453 |
| कन्वेंस डीड जारी | 19,293 |
| अस्वीकृत आवेदन | 31,389 |
| लंबित आवेदन | 64,087 |
| आवेदक के स्तर पर लंबित मामले | 60,473 |
| डीडीए के स्तर पर लंबित मामले | 3,614 |

एप पर लोगों के लिए इस योजना में पंजीकरण करने, आवेदन करने, जीआइएस सर्वे डिटेल भरने व पंजीकरण को प्रिंट करने की सुविधा मोबाइल पर ही उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन एक माह से भी कम समय में यह एप नाकाम हो गया है। अब यह एप खुल नहीं रहा है। लोगों के अनुसार एप खोलने पर अपडेट को-आर्डिनेट करने वाली एजेंसियों

- साढे तीन वर्ष में 19 हजार लोगों को ही मिल सका संपत्ति का मालिकाना हक
- डीडीए का कहना है कि प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोशिश की जा रही है

अपडेट कहां से होगा, नहीं पता। न तो गुगल प्ले स्टोर और न ही डीडीए के लिंक पर इसे अपडेट करने की कोई प्रक्रिया दी गई है। साथ ही एप खोलने पर यह भी लिखा आ रहा है कि हम इसमें कुछ फीचर जोड़ रहे हैं और कुछ बचे इश्यू हल कर रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके। दूसरी ओर पीएम उदय योजना में आवेदन कर चुके लोगों के अनुसार स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। इसमें संपत्ति के कागज की पूरी चेन सबसे बड़ी बाधा है। वहीं, अब तक जीयो रिक्वायर्ड आ रहा है, लेकिन यह को भी कई बाद बदला जा चुका है।

NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2023 **दैनिक जागरण**

अंडर–14 फ्रीस्टाइल और बैकस्ट्रोक स्वीमिंग में अनिष्क व प्रज्ञा को स्वर्ण

सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में स्कूल स्तर के खिलांड़ियों के लिए स्वीमिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया। टर्नामेंट का आयोजन फ्रीस्टाइल और बैकस्टोक श्रेणी में अंडर-10 व अंडर-14 वर्ग के बालक व बालिकाओं के लिए किया गया था। इसमें एनसीआर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया था। परिणाम की बात करें तो अंडर-14 फ्रीस्टाइल के बालक वर्ग में अनिष्क रावत ने स्वर्ण, देव भारद्वाज ने रजत व जप मल्होत्रा ने कांस्य पदक हासिल किया, वहीं बालिका वर्ग में प्रज्ञा तिवारी ने स्वर्ण, जाह्नवी सिंह ने रजत जीता और मधुष्का राठी को कांस्य से संतोष करना पड़ा। अनिष्क रावत और प्रज्ञा तिवारी ने अंडर-14 बैकस्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक झटका।

कोच सिंदू ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की े ओर से खेल प्रिरिसरों में प्रत्येक टूर्नामेंट में एनसीआर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिया था भाग स्वीमिंग टूर्नामेंट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले सम्मानित



यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में स्वीमिंग टूर्नामेंट के विजेताओं को पदक देकर सम्मानित करते सर्विव कर्नल नवाब सिंह(बाएं) व अन्य 🏽 जागरण

महीने एक विभिन्न प्रतिस्पर्धा का विजेता खिलाडियों को सम्मानित आयोजन किया जाता है, जिसका किया गया। इस मौके पर कांप्लेक्स उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति सजग के सचिव कर्नल नवाब सिंह, व उनकी प्रतिभा को मैदान पर सहायक प्रबंधक राम अवतार शर्मा, निखारना होता है। स्वीमिंग टूर्नामेंट पदाधिकारी देवानंद व अन्य लोग में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले मौजूद रहे।

10 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2023

दिल्ली

-DATED-

बाढ़ से मिले झटकों की भरपाई में जुटा प्रशासनिक अमला

13 दानिक्स व प्रोबेशन पर चल रहे दो आइएएस अधिकारी कार्य में जुटे



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से संबंधित तैयारी को हाल ही में वर्षा और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ। आयोजन का समय करीब आने के साथ तैयारी को समय से पुरा करने के लिए घडी की सुई की रफ्तार से काम किया जा रहा है। इस काम को अंतिम रूप देने में पूरा प्रशासिनक अमला जुटा हुआ है। एलजी वीके सक्सेना ने तैयारियों से संबंधित कार्यों को पूरी रफ्तार देने के लिए प्रोबेशन चल रहे 13 दानिक्स एवं दो महिला आइएएस प्रोबेशनर अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है।

कई टीमों में बंटे ये अधिकारी जी-20 शिखर सम्मेलन में जुड़ी सड़कों, होटलों, कार्यक्रम स्थल के आसपास तैयारी का निरीक्षण करते हैं। इन लोगों के साथ मरम्मत से जुड़े सभी साजों सामान से लैस टुक चलते हैं। साथ में पीडब्ल्यूडी,

सम्मेलन से जुड़ी सड़कें, कार्यक्रम स्थल के आसपास का करते हैं निरीक्षण, साजो सामानों से लदा टुक चलता है साथ

एनडीएमसी, एमसीडी व वन विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। टीम जहां भी किमयां देखती है, मसलन कहीं गमला, पौधे व सड़क टूटी देखते हैं, तो उसे तुरंत दुरुस्त कराते हैं। इसी तरह दिन और रात निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दिल्ली सरकार की मदद कर रहे हैं।

नए सिरे से प्रगति कार्यों का जायजा लेने और सभी एजेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एलजी के निर्देश पर जिला निगरानी समितियों में एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी समन्वयक के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित डीएम, डीसीपी, एमसीडी के डीसी एनडीएमसी के सचिव और डीडीए के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। इन समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कमियों का विश्लेषण उन्हें पूरा करने के लिए बनाया गया है। इन्हें

संबंधित विभाग की मदद से किमयों को दूर करने का अधिकार दिया गया है। पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, एमसीडी व वन विभाग की नर्सीरेयों का निरीक्षण करने के लिए इन अधिकारियों को अतुल सोनी, शैली, तुषार आनंद और सुशांत पाधा की अगुवाई में तीन-तीन लोगों की टीम में बांटा गया है। यह टीम राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित नसीरियों में जाकर उपलब्ध पौधों का जायजा लेती हैं और कहां कौन से पौधे लगाने हैं, उसकी पहचान करती हैं। ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन होटलों तक सड़कों का निरीक्षण भी शामिल है, जहां शिखर सम्मेलन के दौरान जी-20 में शामिल होने वाले मेहमान ठहरेंगे। आइएएस अधिकारी अमन सिंह लोहान इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। ये प्रोबेशन पर चल रहे आइएएस के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्रत्येक जिले में समन्वयक के रूप में नामित किया गया है।



क्या एनसीआर में स्टेडियम, खेल परिसरों व पाकों में सिंचाई के लिए भूजल का दोहन किया जाना उचित है?



क्या आप मानते हैं कि एनसीआर में एसटीपी से शोधित जल का अधिकतम उपयोग सनिश्चित नहीं हो पा रहा है?



मददा से संबंधित अपनी राय. सुझाव और प्रतिक्रिया

पर भेज सकते हैं।

दैनिक जामरण IV नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2023 www.jagran.com

शोधित जल के उपयोग की दिखानी होगी इच्छाशक्ति



पूर्व सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल दोहन और सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के शोधित जल की बर्बादी बड़ी समस्या है। इसके सदुपयोग से राजधानी में पानी की किल्लत दूर की जा सकती है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक रच्छाशक्ति व नियमों को जमीन पर लागू कराने की जरूरत है। नियम तो हैं, लेकिन उसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। स्टेडियम, पार्क सहित अन्य स्थानों पर दुयुबवेल लगाकर पानी लिया जा रहा है। इससे भूजल स्तर गिर रहा है। इसे रोककर शोधित जल के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। जल की आपूर्ति की जाती है। विभिन्न विभागों दिल्ली में धरातलीय जल की उपलब्धता को पाकों में सिंचाई व अन्य काम के लिए सीमित है। यहां गंगा, यमुना व रावी व्यास पानी देकर इसे बढाया जा सकता है। से पानी पहुंचता है। नंगल बांध से रावी व्यास का पानी परिचमी यमुना नहर में लाया जाता है। प्रस्तावित रेणुका, किशाऊ व लखवर व्यासी बांध बनने के बाद ही दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है। इस स्थिति में बद्दती जनसंख्या को पानी आपूर्ति के लिए भूजल पर निर्भरता बद्द रही है। अधिकृत व अनधिकृत कालोनी में अवैध तरीके से

उपयोग हो सकता है। वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार डीडीए के जिला पार्कों के 110 ट्यूबवेल में से 59 का पानी पीने योग्य नहीं था। खराब पानी का उपयोग पार्कों में सिंचाई के लिए किया जाता था। इन पार्कों के नजदीक एसटीपी संयंत्र थे

लगभग 250 एमजीडी भूजल दोहन हो रहा

है। सबसे ज्यादा अनिधकृत कालोनियों में अवैध ट्यूबवेल लगे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र

में भी भूजल का उपयोग होता है। ओखला

औद्योगिक क्षेत्र में नौ मिलियन लीटर

प्रतिदिन (एमएलडी) का एसटीपी लगा था।

आँद्योगिक इकाइयों को इससे पानी दिया जाना

था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लगभग

सभी सरकारी विभाग भूजल दोहन कर रहे

हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

की कालोनी व पार्कों की संख्या ज्यादा है

इसलिए यहां शोधित जल का सबसे ज्यादा

और वहां से पानी लाने के लिए पाइपलाइन व अन्य उपकरण लगे हुए थे, लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण खराब हो गए। यहीं स्थिति नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम, रेलवे. लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों का है। सरकारी विभाग एसटीपी संयंत्र से पानी लेने के लिए पाइपलाइन बिछाने व अन्य जरूरी संसाधन पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें बाध्य भी नहीं किया जाता है। इस कारण एसटीपी की जगह भूजल दोहन कर रहे हैं। इसे रोकना जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड वर्ष 2012-13 में विधिन्त विधारों को शिंचार्ट के लिए व बिजली संयंत्रों को 89 एमजीडी शोधित पानी देता था। कृषि योग्य भूमि पर वैध व अवैध आवासीय कालोनियां बनने से सिंचाई कार्य के लिए व बिजली संयंत्रों को 70 एमजीडी से भी कम एसटीपी से शोधित

दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को 40 एमजीडी शोधित जल जरूरत है, लेकिन मात्र 20 एमजीडी आपूर्ति होती है। पुरानी पाइपलाइन होने के कारण 20 एमजीडी से ज्यादा पानी देने से उसमें खराबी आने लगती है। नई पाइपलाइन बिछाकर एनडीएमसी क्षेत्र में शोधित जल की खपत बढ़ाई जा सकती है। डीएमआरसी को 10 एमजीडी पानी दिया जा सकता है। रेलवे कोच की धुलाई और ट्रेनों के शौचालय के लिए शोधित पानी देकर भूजल दोहन को कम किया जा सकता है। वन विभाग को भी धनल की जगह शोधित जल के तपयोग के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इन प्रयासों से राजधानी के पार्कों में लगे एक हजार से ज्यादा ट्यूबवेल बंद कराए जा संकते हैं। राजधानी जल स्रोत लुप्त होते जा रहे हैं। एसटीपी के शोधित जल से इनकी दशा सुधारी जा सकती है। वायु प्रदूषण कम करने में भी शोधित जल सहायक हो सकता है। कई विकसित शहरों में सड़क के सेंट्रल वर्ज पर पाइपलाइन बिछाकर शोधित जल से सड़कों पर छिड़काव किया जाता है। दिल्लो में भी इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है।

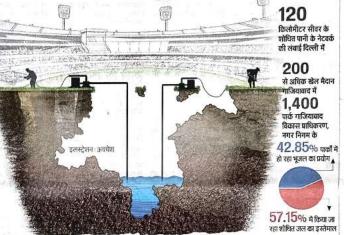
– संतोष कुमार सिंह में बातचीत पर आधारित

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दिल्ली रिश्वत अरुण जेटली स्टेडियम को सींचने के लिए तीन बोरवेल के जरिये प्रतिदिन 100 किलोलीटर भजल का दोहन किया जा रहा है। एनसीआर में सिर्फ यही एक रटेडियम नहीं है। दिल्ली में कई रटेडियम होने के साथ ही नोएडा, गाजियावाद, गुरुग्राम और फरीदावाद में भी विभिन्न स्टेडियम, खेल परिसर और पार्क हैं, जहां सिंवाई के लिए वड़े पैमाने पर भजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पानी शोधित किया जा रहा है वहां से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकारी विभागों की लापरवाही से शोधित पानी

नालों में वहाया जा रहा है। वड़ा सवाल यह है कि आखिर स्टेडियम, खेल परिसरों व पार्कों में शिचाई के लिए शोधित पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? भूजल दोहन पर निर्भरता क्यों है? सीवरेज के शोधित जल से स्टेडियम, पार्की में सिचाई क्यों नहीं की जाती? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सीवरेज का जल शोधित कर स्टेडियम, खेल परिसरों व

पार्कों को उपलब्ध कराने के लिए क्या किए जाने चाहिए तोस उपाय? कैसे एसटीपी के शोधित जल का उपयोग अधिकाधिक बढाया जाए? भूजल दोहन कम किया जाए? इसी की पड़ताल करना हमारा आज का मुद्दा है :

दोहन से सुख रही धरा



कहां और कैसे हो रहा भूजल दोहन

- डीडीए व अन्य सरकारी विभागों के पार्कों में
- वन विभाग में सिंचाई के लिए
- रेलवे व दिल्ली मेट्रो रेल निगम में कोच की सफाई
- स्टेशन की सफार्ड व अन्य कार्यों में

- वडे व छोटे स्टेडियम में सफाई

राजधानी में कुल भूजल दोहन एसटीपी क्षमता (एमजीडी)

डीडीए, पीडब्ल्यूडी

- व अन्य विभागों में निर्माण कार्य के लिए
 - सिंचाई व अन्य कार्य के लिए
 - औलोगिक टकाटमों में

एसटीपी से शोधित जल का उपयोग

- दिल्ली के विजली उत्पादन संयंत्रों में
- कुछ सरकारी विभागों के पाकों में सिंचाई के लिए
- एनडीएमसी क्षेत्र में सिंचाई व सफाई के लिए
- झीलों व जलाशयों को पुनर्जीवित करने में
- नई झील व जलाशय में

विकसित किया जाए बुनियादी ढांचा, आनलाइन हो निगरानी



प्रोफेसर, भूगर्भ विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्टेडियम, खेल परिसरीं और पार्की में सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है। इससे भूजल के स्तर में तो गिरावट आ ही रही है, दूसरी ओर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) का शोधित पानी बगैर इस्तेमाल के व्ययं हो रहा है। अगर एसटीपी शोधित इस पानी का सही ढंग से इस्तेमाल हो जाए तो भूजल दोहन पर रोक लग सकती है। इसके लिए कोई लंबी-चौड़ी मशक्कत भी नहीं करनी, ढूढ़ इच्छाशक्ति के साथ थोड़े से प्रयास भर करने हैं।

स्टेडियम, खेल परिसरों और पाकौँ जैसे अंतिम उपयोगकर्ताओं को पाइपों से या टैंकरों के माध्यम से सीवरेज के शोधित जल की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए वांछित बुनियादी ढांचा विकसित तैयार करने की जरूरत है। खासकर उन सभी क्षेत्रों में जहां भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया है, जल स्तर की गहराई आठ मीटर से अधिक है एवं जल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। यहां अविलंब यह द्रांचा तैयार करना समय की मांग है। मेरा मानना है कि केंद्रीय भजल प्राधिकरण/राज्य भजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यए/एसजीडब्ल्यए) स्टेडियमॉ/ पार्कों आदि में एसटीपी उपचारित पानी की आपूर्ति को अनिवार्य बनाना चाहिए। इससे भूजल दोहन पर दबाव कम होगा। रम प्रक्रिया को कियाशील बनाने के लिए एसटीपी से उपचारित पानी की लगातार आनलाइन निगरानी भी होती रहनी चाहिए ताकि सनिश्चित हो सके कि यह सिंचाई मानक के अनुरूप है।

मेरा यह भी मानना है कि सीवरेज के जल को शोधित पानी में पुनर्चक्रित करके दिल्ली की मूजल प्रणाली पर तनाव कम किया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की वर्ष 2017 के लिए दिल्ली में पानी की मांग 1140 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) थी। वर्ष 2023 में 30 से 40 एमजीडी अधिक, मान लीजिए 1170 एमजीडी हो गई। दसरी तरफ, वर्तमान में डीजेबी द्वारा कल वर्तमान जल उत्पादन लगभग 1000 एमजीडी है। यदि हम 20% की दर से पानी के लीकेज को ध्यान में रखते हैं, तो दिल्ली के हितधारकों तक पहुंचने वाला पानी लगभग 800 एमजीडी है। इससे 370 एमजीडी की कभी होती है। इस लीकेज को रोककर भी भजल पर निर्भरता घटाई जा सकती है।

हाल ही में केंद्रीय मूजल प्राधिकरण राजंपत्र अधिसूचना में भी निर्दिष्ट किया गया है कि पीने के पानी, घरेलू उपयोग और कृषि गतिविधियों के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं को भूजल दोहन के लिए अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगने से छूट दी गई है। मौजूदा स्थिति के संदर्भ में, जब व्यक्तिगत हितधारकों को उनके उपयोग के लिए पर्याप्त पानी की आपर्ति नहीं की जाती है तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल टोइन सबसे आसान विकल्प है। उससे दिल्ली के अतिदोहित ब्लाकॉ में भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प दिल्ली में उपलब्ध 607 एमजीडी की अपशिष्ट जल उपचार क्षमता का उपयोग करना होगा। दिल्ली की बदती आबाटी भी यहां की गोधित जल प्रणाली में सीवरेज के पानी के पनर्चक्रण को अधिकतम करके विकास के प्रतिमान में बदलाव की इच्छा रखती है।

-संजीव गप्ता से बातचीत

किए कराए पर फेर रहे पानी

सरकारी विभागों के पार्कों से लंकर वन विभाग और रेलवे तक कहीं पेसी जगह नहीं है जहा गर भागल दोहन करके सिवार्ड जहीं हो उही हो। अब भगती की कोख से जल सोखकर पार्कों को हराधरा कर रहे हैं और एसटीपी का शोधित पानी त्यर्थ जा रहा है। सरकार, प्रशासन दूसरों की पानी बचाने और शोधित जल के इस्तेमाल के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर खुद इस पहल में नहीं खड़े हैं।



ओखला चरण छह 🌉 हेक्टेयर मीटर एसटीपी से शोधित

36267.34 हेक्टेयर वार्षिक भूजल रिचार्ज 41051.64

महरौली: 5

ओखला चरण तीन

ओखला चरण दो 12

ओखला चरण पांच 🔤 16

570 एमजीडी भूजल का

डा . सेन नर्सिंग होम नाला 🛮 2.2 वसंत क्रंज चरण एक 2.2 वसत कुंज चरण दो 📲 3

मोलडबंद : 0.66

दिल्ली में वालू स्थिति में एसटीपी

से शोधित हो रहा है

कॉडली बरण एक 110 कोंडली चरण तीन 💹 10 कोंडली चरण चार 35 एसटीपी की कुल क्षमता : 632 एमजीडी एसटीपी 570 एमजीडी (कुल

घिटोरनी : 5

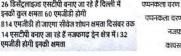
दिल्ली गेट नाला चरण एक 2.2

दिल्ली गेट नाला चरण दो _____15

क्षमता का 90.2 विस्तार के %) दिसंबर तक एसटीपी साथ कुल क्षमता 744 एमजीडी हो जाएगी



- 26 डिसेंटलाइज्ड एसटीपी बनाए जा रहे हैं दिल्ली में
- इनकी कुल क्षमता 60 एमजीडी होगी 814 एमजीडी हो जाएगा सीवेज शोधन क्षमता दिसंबर तक
- 14 एसटीपी बनाए जा रहे हैं नजफगढ़ ड्रेन क्षेत्र में। 32





11 एसटीपी हैं एनडीएमसी इलाके में 122 एनडीएमसी कालोनी पार्क हैं

2.850 केएलडी प्रतिदिन शोधित पानी को सिंवाई के लिए

उपयोग किया जाता है। 450 कालोनी पार्क सीपीडब्ल्यूडी के एनडीएमसी के पास है



- दो स्टेडियम नगर निगम के प्रवेश साहिब सिंह बर्मा स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम
- 32 एसटीपी लगा रखें हैं एमसीडी ने. शोधित पानी का पार्को में सिंचाई के लिए होता है उपयोग
- 3000 से ज्यादा पाकों में ट्यूबवेत वंद करने के लिए 300 करोड़ की लागत से लगने हैं एसटीपी
- वेपकोस ने एक डीपीआर बनाकर दिल्ली जल बोर्ड को जमा की

गौतगबुद्ध नगर में पानी की कहां कितनी खपत (एमएलडी में) 135 स्टेडियम, खेल ਪਰਿਟਿਜ स्टेडियम, खेल शोधित प्रतिदिन परिसर व पार्क परिसर व पार्क में जल से एसटीपी भूजल दोहन सिंचाई सिंचार्ड शोचित पानी पानी की खपत

गुरुग्राम में शोधित पानी का उपयोग (एमएलडी में)

बागवानी 30 टेक्सटाइल इडस्ट्री 🛮 5 निर्माण कार्य 🖥 9 तालाब और वन क्षेत्र 🛙 7 कृषि सिंचाई आदि 30% कुल शोधित पानी का उपयोग हो रहा है.

गरुग्राम : 1200 पार्क 30 एमएलडी से ज्यादा शोधित पानी पार्कों में

80 एमएलडी भुजल दोहन

• 126 एमएलडी पानी एसटीपी 570 एमएलडी नहरी पेयजल आपूर्ति

जिले में दो प्राने एसटीपी

- बहरामपुर एसटीपी की कुल क्षमकः 170 एमएल
- धनवापुर एसटीपी की क्षमता 218 प्रमुप्तडी
- 100, 68 और 50 एमएलडी की तीन यूनिट 120 व 50 एमएलडी की दो यूनिट

Hindustan Times MY DELHI

How 1947 changed Delhi: The evolution of city post Partition

Charting Delhi's growth

Two maps chart Delhi's sharp urban growth after hundreds of

NEW DELHI: Historian Mridula Mukherjee was born in a Kamla Nagar apartment three years after Partition. Her parents, pro-fessors from Lahore, made Delhi lessors from Lahore, made Delhi their new home and started teaching. The initial years were difficult as both the city and the refugees were still coming to terms with the changes and challenges that the mass migra-tion brought. Her father started teaching at Camp College set un near Mon-

Her father started teaching at Camp College, set up near Man-dir Marg, that gave degrees affili-ated to Panjab University. It held evening classes as it was mainly for refugees who were from Lahore University. "All of these people had left everything behind and had to work jobs during the day, and could only attend classes in the evening. My mother became a schooleacher at a municipal school near Gole Market as it was the only thing she could find during all the tu-moil," said 73-year old Mukher-jee, a chronicler of modern India.

The sociolinevistic comments as the said of the socio-

The sociolinguistic composi-tion of Delhi changed radically and quickly over that initial decand quickly over that initial dec-ade, she remembers. The city expanded far beyond the exist-ing Shahjahanabad area of Old Delhi, and the still-young enclave for the British in New Delhi — to the area south of Loddhi Garden that had been farmland and forest till then.

Influx of refugees Between 1941 and 1951, Delhi's Between 1941 and 1951, Delhir's population shot up by 90%, an increase that was never seen before or after those years in the national capital. These were the years when refugees from Padistan came to India, most of them to Delhi. Many of them built the Delhi we know today.

Settling and integrating these people into the city and the country was not an easy task, especially considering the numbers. As per census numbers.

bers. As per census numbers, following the promotion of Delhi as the capital of the British Indian Empire in 1911, the population grew from 238,000 in 1911 to 696,000 in 1947. The census to 696,000 in 1947. The census has an official record of 459,391 "displaced people" who moved to Delhi in 1947, almost doubling the population of the city. What is historically known as

one of the largest migration of people across borders, Partition affected Delhi the most, throwaffected Delhi the most, throw-ing all planning for the national capital out of gear. The meticu-lously planned New Delhi designed by British architect Sir Edwin Lutyens, became a glori-fied refugee camp in a matter of days. "In 1947, the population of Delhi was around 7 lakh

(700,000). Within two months between July and September, about 5 lakh people came to Delhi and the population was suddenly 12 lakh (1.2 million). People just overtook whatever space they could find. The initial space they could find. The initial camps were in Purana Quila and Firoz'shah Kotla, but eventually, the entire city was flooded by people who occupied roads, public parks, closed schools, areas around Connaught Place or any other open area that they found. The government tried its best to provide ration, food, medicine, tents and other facilities but resources were limited." said A K resources were limited," said A K Jain, one of the first commissioners of Delhi Development

Authority (DDA). New Delhi was declared the New Delhi was declared the capital of India in December 1911 and the people who settled in it thereafter were mainly government officials. This sudden pouring in of lakhs of people into the city posed a major challenge for the government which had been planning a city for the urban clite based on the British and American design philosophies. They were planning a ring-

They were planning a ring-and-radial patterned city. Rai-sina Hills emulated the Arc de Triomphe in Paris. This garden Triomphe in Paris. This garden city was supposed to have a one-acre park for every 10 acres of residential area. Suddenly, the entire focus shifted to accommodating more people in less area; aid PS Uttarwar, retired additional commissioner of DDA. The government soon constituted a Ministry of Refugees that took care of the facilities at the camps. It operated for about a year, after which it was converted to the Ministry of Rehamer of R

verted to the Ministry of Reha-bilitation (MoR). According to letter from the Prime Minist Office (PMO) available in the National Archives, official orders from the PMO in 1947 stated that

gravity of a national emergency.

KK Balli was three years old when he moved to Delhi in 1952 with his father. His family shifted from Pakistan to the Indian side of Punjab months before Independence to stay with relatives. After spending the initial few years in parts of Punjab and Haryana, the family moved to Delhi.

The first few years just went into trying to move around till things were more peaceful, but

things were more peaceful, but Delhi was ultimately the place to Delhi was ultimately the place to go if you came from Pakistan. My father also found his footing once he moved here. We found rented accommodation initially in Gandhi Nagar as most of the other areas were already crowded. My father got a govern-ment job as he was well edu-cated. After a few years, we bought land in the same area and built a house. Our fourth and built a house. Our fourth generation is living in that house now," said Balli, a businessman based in Gandhi Nagar.

Settlements across city The Baseline Report for Delhi Master Plan 2041 states that by December 1950, accommodation for 100,000 refugees was con-structed in 21 colonies by MoR, structed in 21 colonies by MoR, which included Azadpur, Rajinder Nagar, Patel Nagar, Shakti Nagar, Kingsway, Tilak Nagar, Gandhi Nagar, Krishan Nagar, East Nizamuddin, Jangpura, Lajpat Nagar, Kalagli, Geeta Colony, Shekib Saral, Rajouri Garden, and Malviya Nagar.

By 1955, 15 more colonies were added as people who left Pakistan continued to pour into the city till the late 1950s.

"My grandfather belonged to the Jhang district of Pakistan on where his sister's husband was killed during Partition. He left

thousands of refugees made the city their home after Partition Delhi's growth from How Delhi changed from 1930-1947 1947-1962 Growth Growth Old Delhi Lodhi Estato Late colonial period (After partition)

- By 1950, the ministry of rehabilitation (MoR) built accommodation for 100,000 refugees in 21 colonies in Azadpur, Rajendra Magar, Patel Nagar, Shakti Nagar, Ritak Magar, Gandh Nagar, Krishna Nagar, East Nizamuddin, Jangpura, Lajpat Nagar, Kashali and Malviya Nagar, among others

- By 1953, Golf Links, Jor Bagh, and others came up in the south. The projects were planned and designed by the Dehi Improvement Trust (DTT, set up in 1937)

- Richted colonies (Na Paleirus Cardias, South Delhi was comprised of areas like Walled City and settlements such as Civil Lines, Paharganj, Sada Bazar, Delhi Cantonment, among others Developments from 1930-1947

Development of southern part of Davagang, which was onginally a garden and orchard

Development of Western Extension Area in Karol Bagh catering to a population of 53,000

Sujan Singh Park, bulk in the mid-405 by a developer called 5r Shobha Singh. The project introduced 'apartment-living' on an 'ownership' basis for the first time in Delhi Plotted colonies like Rajouri Garden, South Extension, Greater Kallash, Kallash Colony, Green Park, Hauz Khas, and more, were built by private Delhi Development (Provisional) Authority (DDPA) was constituted in

moved to Rajasthan with his sis-ter's family. They were given wasteland as compensation in Loharu area of Rajasthan. He Loharu area of Rajasthan. He knew that moving to Delhi was the only way to prusper. My family moved here in 1953 and my grandfather worked odd jobs before he started a garment business. Delhi was all about the railway stations and parts of Old Delhi areas initially. Everything else was deserted. We lived in Shahdaru, which had one police station that time; there are over 30 notice stations now." said 30 police stations now," said Naresh Sikka, a businessman in

Naresh Sikka, a businessman in Shahdara.

Some areas saw residents from a particular area in Pakistan settling, and took on names that reflected this. Thus came about Punjabl Bagh, Gujranwala Town, and Derawal Nagar.

The people who moved into camps were initially given refugee cards that were replaced with provisional ration cards and other identification as the

and other identification as the and other identification as the government started allotting houses to them. Officials say that the government allotted a total of 70,000 plots across these colonies to displaced people against a nominal rent. About 10,000 other plots were allotted free of core with small rooms built on cost with small rooms built on them with asbestos sheet roofing for those who were poor

"Most of the allotted plots were 80-100 square yards in size. The allottees had to pay a monthly instalment of #12 and 50 paise for 15 years. Later as the government realised that space was limited, some smaller plots of 50-60 square yards were also added. One of the most farsighted things done by the government was the acquisition of large land parcels from farmers in 1912-13, which made it possible to chart out these colonies," said Jain.

City's expansion He added that the Indian govern-ment acquired around 10,000 acres to build "New Delhi" and another 10,000 acres for the cantonment. In addition, it acquired another 30,000 acres for extending the city. On this land came ing the city. On this land came up Najafgarh, Rajouri Garden and Janakpuri as extensions to the west, Karol Bagh and beyond towards the south and parts of Kamla Nagar. Roop and Shakti Nagar towards the North.

These "Fetipaes" colonies turil.

Nagar towards the North.
These "refugee" colonies, typi-cally U-shaped developments with a park in the middle, became the template for subse-quent neighbourhoods, partly because they were built by the same urban planners who shaped Delhi through the 50s and 60s. This was the beginning of Rajinder Nagar, West Patel

Nagar, Mott Nagar, and Rajouri Garden. By the middle of the 1950s, 'refugees moved into empty flats in Lodhi Colony and built homes around the villages in Nizamuddin and Jangpura. All of this was on what was once the deserted south side of Lodhi Road.

By the end of 1950, the govern-ment had allotted nearly 2,958 acres and housed 300,000 refused from the control of the control from the control of the control from the control of the control of the control of the control of the control from the control of the co

nouses and 100,000 in newly constructed houses. The govern-ment also set up a Rehabilitation Finance Administration to over-see monetary aid to refugees who needed it. Delhi also pro-vided aid for small shopkeepers, relief schemes, grants, loans to suddent and those who woorld students, and those who wanted

to start businesses or industries. Business boomed. In 1953, the Business boomed. In 1953, the city's growing middle class con-tributed to the growth of Delhi significantly and building activ-ity accelerated. By the mid-1950s, elite neighbourhoods of Golf citic neighbourhoods of Loulinks, Sunder Nursery, Jor Bagh, etc. with large plot sizes from 400 square metres to 1.000 square metres came up in the South. The projects were planned and designed by Delth Improvement Trust and exeplanned and designed by Decid Improvement Trust and exe-cuted by L&DO (Land and Devel-

opment Office).

By then DIT's role and effectiveness was already being ques-

tioned. And the government also realised that the planning of Delhi could not continue to be restricted to haphazard allotment of colonies.

"After partition of the country, in 1947, there was enormous population influx into Delhi, which exceed herberard growth

population influx into Delhi, which caused haphazard growth of colonies, land encroachment and creation of slums, scarcity of the resources, pressure on accommodation facilities, etc. accommodation facilities, etc. DIT tried various city expansion schemes, but was compromised by land speculation and little access of the new areas to the city's poor. DIT's role came under massive criticism after Independence," said the baseline report for MPD 2041. The GD Birla committee, appointed to investigate the DIT's working and social mandate in 1950, undertook a com-

date in 1950, undertook a comdate in 1950, undertook a com-prehensive review of the organi-sation's work and in a report presented in 1951 said DIT had failed to provide a healthy civic environment in the city, provide housing to the poor , resulting in the unplanned growth of the city without effective zoning or a comprehensive Master Plan. Eventually, the Dehli Develop-ment (Provisional). Authority

Eventually, the Delhi Develop-ment (Provisional). Authority (DDRA) was constituted in 1955; DDA was formed in 1957(the allotment of plots to the refugees went on till the early 1960s). In 1958, after staying at the rented accommodation in Kamla Nagar for Il years, Mridula Muk-herjee's parents were allotted a plot in Lajast Nagar. Mukherjee was eight when she moved to her bouse in Lajpat Nagar, she spent house in Lajpat Nagar, she spent her entire childhood and adoles-

her entire childhood and adoles-cent years there.

"Lajpat Nagar 1, 2 and 4 had smaller houses that were built by the government and allotted. Lajpat Nagar 3 had the bigger plots that were allotted against a nominal price to people who could afford them. My father had taken one of these bigger plots," said Mukherjee, former chair-person of the Centre for Histori-cal Studies at Jawaharlal Nehru University. University

Evolving Capital
Lajpat Nagar was "quiet" compared to the busy thoroughfare it stoday, she recollects. "Lajpat Nagar was a residential colony of middle-class professionals and not the specialized accreant not the specialised garment market that everyone visits these days. The market there was a days. The market there was a colony market that residents would visit for their daily grocer-les, medicines or for an evening chat or to get your pictures framed. It was a close commuty neighbourhood where everyone knew everyone. Hardly anyone had cars. So, we would with the colon of the picture of the colon of the picture and it was safe to do that," said Mukheries.

Mukherjee. Across the road was Defence Across the road was Defence Colony, which was settled around the same time by mili-tary officials. She remembers it as a favourite hang-out with good bakeries, "We had school friends from Defence Colony and we would walk across the road to have an éclair or patty at the to have an ectair of party at the bakeries there. I cannot even imagine anyone walking across the Link Road today from Lajpa Nagar to Defence Colony," adds Mukherjee, who lived at the JNU campus as a faculty member for 40 wors.

She moved back to her Lajpat Nagar childhood home four

years ago after retiring.

The first Master Plan of Delhi was finally prepared in 1962 by DDA and the Town and Country Planning organisation with technical assistance from the Ford Econdation.

Foundation.
And the city never looked

Hindustan Times

NEW DELHI WEDNESDAY AUGUST 16, 2023

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 16 अगस्त 2023

2-day Assembly meet from today, fireworks likely

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A two-day special session of the Delhi assembly is scheduled to begin on Wednesday, with the ruling Aam Aadmi Party likely to raise the issue of the recently enacted Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023, while the opposition Bharatiya Janata Party is geared up to question the government on various issues, including the alleged mismanagement of the recent floods, and the reconstruction of chief minister Arvind Kejriwal's official bungalow.

The Delhi assembly has 70 members — 62 from the AAP, and eight from the BJP.

According to officials aware of the Assembly schedule, the House will begin at llam with obituary references, following which the members will be able to raise matters under Rule 280 with the permission of the chair. Rule 280 (special mention) is a device for legislation to draw the attention of the government to issues relating to their constituency, or other developments.

After this, the officials said, minister Atishi will lay various papers on the table, including a notification regarding the Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2023.

On the eve of the session, BJP legislators, at a joint press conference, accused the AAP of undermining democracy. "Over

the last three years, BJP MLAs have been marshalled out or suspended from the Assembly 35 times in 16 sessions. The ruling AAP has stifled Opposition voices by preventing discussions on notices raised by BJP legislators. This time also, no question hour has been included in the session because the government does not want to answer questions," said Leader of Opposition Ramvir Singh Bidhuri.

He added that BJP MLAs have given a notice for a short duration discussion on 12 "scams" under Rule 55, which allows legislators to draw the attention of the government to matters of urgent public importance. "We have drawn a list of 12 scams and we want a discussion on all these scams such as the bungalow scam, panic button scam, feedback unit scam, excise scam, among others," said Bidhuri.

Meanwhile, speaker Ram Niwas Goel said that BJP MLAs are given more time to speak in the House than the ruling party members. "...but rather than discussing the issues, they start disrupting the functioning of the House. I have called them to my office to urge them to let the House function, but they do not help in its smooth running," he said. "Questions related to police, land, and services were earlier answered in the House, but now questions related to land, services, DDA, revenue are not submitted by the officers. In such a situation, what is the point of including the question hour?"

विकास मार्ग : मार्केट में सीवर ओवरफ्लो

एनबीटी न्यूज, न्यू राजधानी एनक्लेव : विकास मार्ग स्थित न्यू राजधानी एनक्लेव में डीडीए ने मार्केट बना रखी है। मार्केट असोसिएशन का कहना है कि वह लोग हर साल टैक्स जमा करते हैं, लेकिन सिविक एजेंसियों की लापरवाही के कारण मेंटिनेंस नहीं की जाती है।

न्यू राजधानी एनक्लेव डीडीए मार्केट लोकल शॉपिंग सेंटर के प्रेजिडेंट जर्नादन गुप्ता ने बताया



कि आज तक इस मार्केट की सीवर लाइन और पानी की लाइन को दिल्ली जल बोर्ड के हैंडओवर नहीं किया गया। इस मार्केट के मेंटिनेंस की जिम्मेदारी न तो डीडीए लेती है न ही दिल्ली जल बोर्ड। सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है। इस बात की शिकायत डीडीए जल बोर्ड और स्थानीय विधायक से भी की जा चुकी है। लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है।



नई दिल्ली बुधवार १६ अगस्त २०२३

विशेषज्ञों की सहायता लेगा डीडीए

नई दिल्ली। डीडीए ने अपने फ्लैटों की बिक्री में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ निजी एजेंसियों को साथ में जोड़ने की योजना बनाई है। इसमें अचल संपत्ति विशेषज्ञ (रियल एस्टेट), निजी व्यापारी एजेंसी को डीडीए जिम्मेदारी सौंपेगा। जिसमें यह डीडीए के सलाहकार के तौर पर जानकारी देंगे कि किन कारणों से राजधानी भर में डीडीए की ओर निर्मित हजारों फ्लैट बिक नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है।

डीडीए चार नए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स शुरू करेगा

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इस वर्ष राजधानी में 4 नए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स शुरू करने जा रहा है। इसमें मैदानी इलाकों व कॉम्पलेक्स के अंदर खेले जाने वाले कई प्रकार के खेलों को खेलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी डीडीए की ओर से दिल्ली भर में 15 स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का संचालन किया जाता है। डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने मंगलवार को नए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को इस वर्ष शुरू करने की जानकारी दी।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, AUGUST 16, 2023

NEWSPAPERS-

DATED

Game For Revenue: DDA To Lease Out Space In 3 Sports Complexes For Ads

To Ink Seven-Year Agreements For Digital And Other Modes Of Promotion

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: For the first time, the Delhi Development Authority (DDA) will lease out spaces inside its three major sports facilities — the Qutab Golf Course, Yamuna Sports Complex and Siri Fort Sports Complex — for displaying digital and other modes of advertisements for a period of seven years.

The authority, keen on exploring other avenues for revenue, has invited applications from interested people and a pre-bid meeting will be called on August 28.

The move has come when DDA is about to inaugurate its Sector 17 sports complex on August 18.

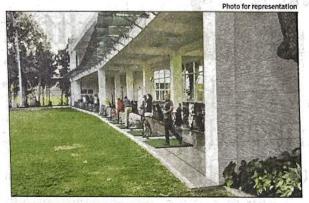
"Though we have been permitting informative advertisements and camps for a week/few days at our sports complexes, this would be the first time we have decided to lease out spaces for seven ye-

ars as per set guidelines and rates. Depending on the bidders' performance, the contract can be increased by two more years," the official said.

The decision will generate revenue in crores and final advertisement rates will be decided after meeting with bidders, said the official further.

Sites for at least 40 digital panels/hoardings/ backlit boards/ unipole in different sizes have been identified and mostly premium products will be displayed here. In addition, 35 small boards are proposed in the parking area.

"Besides commercial utilisation of earmarked advertising spaces, the initiative will contribute to the aesthetic view of the DDA sports complexes/ golf courses through highquality advertising comparable to world-class sports facilities. If required we may increase their numbers on a pro-rata basis," said the official.



TEEING OFF ON A NEW COURSE

The DDA said it has its own policy for leasing out spaces for advertisements inside sports complexes/golf courses.

"At present, the DDA is not liable to share its revenue generated from advertisements inside DDA sports complexes/golf courses with local bodies, including MCD, etc. However, if the DDA becomes liable to share such revenue with local bodies in the future, then it will take a call," the tender document said.

There are 13 categories of advertisements that are prohibited for advertisements. "Unlike metro and other places where footfall goes into lakhs,

we have a limited crowds visiting sports facilities so advertisements will be done accordingly to serve the purpose of the visitors," the official said.

According to the tender document, at Siri Fort Complex, 23 advertisement boards are proposed to be installed, each one of 10x6 sqft in size. These would be around the shooting range, lawn, indoor badminton wall, outside gym wall, outside parking number 2, outside golf driving range, jogging track. There would also be 35 small boards in parking number 1.

In the Yamuna Sports Complex, at least four hoardings (10x15 sqft), five backlit boards (each 8x10 sqft) and a unipole are proposed near the parking area.

At the Qutab Golf Course, eight hoardings (each of 12x12 sqft), one digital board (12x12 sqft) and a backlit board (4x3 sqft) size are proposed to be installed.

NAME OF NEWSPAPERS

🕨 १६ अगस्त, २०२३

आवास बाजार दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने का मामला

डीडीए ने किया निजी फर्म के साथ समझौता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : और मूल्य निर्धारण विधियों की अपनी सूची में 40 हजार से अधिक खाली फ्लैटों की चुनौती से निपटने के प्रयास में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आवास बाजार दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने के लिए एक निजी परामर्श फर्म की मदद ली है। 957 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार, डीडीए ने शहर के आवास बाजार में अपनी उपस्थित को फिर से जीवंत करने के लिए एक निजी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के साथ साझेदारी की है। डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे एक पेशेवर स्पर्श देने के लिए किया जा रहा है, इससे प्राधिकरण और घर खरीदने वालों दोनों को मदद मिलेगी। सलाहकार के कार्य में डीडीए की आवास योजनाओं, आवास मानकों

प्रभावशीलता से संबंधित डेटा की जांच और मुल्यांकन करना शामिल होगा। एजेंसी अपनी खोजों को डीडीए को एक रिपोर्ट में प्रस्तत करेगी. इसमें डीडीए के लिए विचार करने और संभावित रूप से कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव शामिल होंगे। नाम न छापने की शर्त पर डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि आवास बाजार में बदलाव आया है, इससे घर खरीदने वालों को निजी संस्थाओं से विकल्प मिल रहे हैं। इसलिए, उनके पारंपरिक दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अब प्रभावी नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि डीडीए को आवास बाजार में खुद को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए संशोधनों को अपनाना चाहिए।

NAME OF NEWSPAPERS-

-DATED-

Hindustan Times AUGUST 15, 2023



(PERSONNEL BRANCH - 1)
Recruitment Notice

Engagement of Five (05) Consultant (Vigilance)

DDA invites application for engagement of five (05) Consultant (Vigilance) at the level of Asstt. Director (Min.) on contract basis (no. of posts are tentative and may vary as per the requirements of DDA, without prior notice), from retired officers from Central/State/Semi. Govt./PSU/Autonomous or Statutory Organization having substantive pay at the Level 8/9/10/11 in Pay Matrix at the time of retirement and having experience/expertise in ministerial/administrative works like land/housing, CBI/Anti-corruption cases, disciplinary, legal matters, initially for a period of one year or until further orders, further extendable maximum up to 05 years or 65 years of age, whichever is earlier, depending upon the requirement of DDA and performance of the candidate. The upper age limit is 63 years on the last date of receipt of applications. The govt. servants who are due for retirement till last date of receipt of applications can also apply. Applications, complete in all respects should be sent through e-mail to personnelbranch1@dda.org.in latest by 05:00 PM of the last date i.e. 15.09.2023.

The detailed terms & conditions, application format etc. are available in the detailed notice displayed on official website of DDA i.e. www.dda.gov.in in the link 'Jobs'.

Sd/-

(Vineet Jain) Commissioner (Pers.)

NAME OF NEWSPAPERS-

-DATED

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, AUGUST 16, 2023



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE

EMPANELMENT OF SECRETARIES FOR DDA SPORTS COMPLEXES

- DDA has developed and runs 15 Sports Complexes in various parts of Delhi. DDA proposes to empanel retired service officers of the rank of Lt. Colonel (or equivalent from Indian Navy / Air Force) and above, sports persons and retired govt. Servants to manage these facilities as Secretaries.
- For details of eligibility criteria, honorarium and allowances payable, kindly visit jobs page on DDA website, i.e. www.dda.gov.in.
- Applications with a copy of resume, proof of residence and age, recent passport size photograph, phone numbers and e-mail ID may be sent latest by last date 06.09.2023 to Secretary (Coordn.), DDA Siri Fort Sports Complex, August Kranti Marg, New Delhi-110049 (Telephone No. 26496650 /26496657). A copy may also be sent by email to commrsprts@dda.org.in
- 4. Selected candidates would be engaged purely on annual contract basis. Annual extensions of contract would be considered on the basis of performance. Contractual engagement can be terminated by giving 30 days' notice by either party. Maximum tenure would be for 10 years or attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
- Those who have applied in response to notice issued in Times of India "Ascent" dated 04.01.2023 need not re-apply.

Commissioner (Sports), DDA

Follow us on @ddaoffcial @@offcial_dda @@offcial_dda @@offcial_dda Please visit DDA's website at www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800110332